

II. सकल मांग *

सकल मांग में बाह्य तथा निवेश मांग में धीमापन आने से गिरावट आई। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निर्यात के प्रभावित हुआ और बाह्य मांग में गिरावट आई। 2011-12 की दूसरी तिमाही में कंपनियों के जारी निवेशों में तेजी से गिरावट आई। निजी उपभोग में गिरावट क्रमशः जारी है जबकि सरकारी उपभोग व्यय में वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार के घाटा संबंधी संकेतक सब्सिडियों के उच्चतर रहने तथा अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के कारण कर संग्रहण में कमी आने से दबाव में आ गए। आगे चलकर पहले की उच्च वृद्धि दर को हासिल करने तथा संभावित वृद्धि दर को और आगे ले जाने के लिए सार्वजनिक व्यय को उपभोग से निवेश की ओर ले जाने की जरूरत होगी।

गिरते बाह्य तथा निवेश मांग के चलते 2012-13 की वृद्धि दर घट सकती है

II.1 2011-12 की पहली छमाही में घटते निवेश तथा संकुचित होती बाह्य मांग के साथ-साथ उपभोग मांग में गिरावट आने से बाजार

मूल्यों पर जीडीपी की वृद्धि दर घटकर 7.6 प्रतिशत रह गई (सारणी II.1)। उच्च मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में मांग में गिरावट आने से खपत में गिरावट आई। निवेश में मौद्रिक तथा गैर-मौद्रिक दोनों ही कारणों से गिरावट आई। 2011-12 की पहली छमाही में निवल निर्यात में तेजी से गिरावट आई जो मुख्यतः वैश्विक मांग में आए धीमेपन को दर्शाती है।

II.2 निवेश में आई गिरावट एवं कमजोर बाह्य मांग का वृद्धि दर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अनुमान दर्शाते हैं कि सकल नियत पूंजी निर्माण दर में एक प्रतिशत अंक की गिरावट से संभावित उत्पादन में लगभग 0.2 प्रतिशत अंक की गिरावट आती है। भारतीय तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चक्र में काफी अधिक समानता दिखाई दे रही है। अनुमान दर्शाते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रतिशत अंक की गिरावट से भारत के गैर-कृषि जीडीपी में लगभग 0.3 प्रतिशत अंक की गिरावट आती है।

सारणी II.1: जीडीपी का व्यय पक्ष (2004-05 के मूल्यों पर)

मद	2009-10*	2010-11#	(प्रतिशत)							
			2010-11				2011-12		2010-11	2011-12
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	छ1	छ1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(वृद्धि दरें)										
बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	9.1	8.8	9.1	8.6	9.2	7.7	8.5	6.7	8.9	7.6
कुल अंतिम खपत व्यय	8.7	8.0	9.1	8.5	7.4	7.5	5.7	5.6	8.8	5.6
(i) निजी	7.3	8.6	9.5	9.0	8.6	8.0	6.3	5.9	9.2	6.1
(ii) सरकारी	16.4	4.8	6.7	6.4	1.9	4.9	2.1	4.0	6.5	3.1
सकल अचल पूंजी निर्माण	7.3	8.6	11.1	10.3	7.8	0.4	7.9	-0.6	10.7	3.5
स्टॉक में परिवर्तन	90.8	7.4	9.3	6.5	5.1	4.6	4.7	1.5	7.9	3.1
निवल निर्यात	10.2	-15.3	33.3	14.2	-52.6	-34.8	21.5	-35.0	23.0	-6.9
(तुलनात्मक हिस्सा)										
कुल अंतिम खपत व्यय	70.1	69.5	72.8	70.9	72.3	63.1	70.9	70.1	71.8	70.5
(i) निजी	58.5	58.3	61.7	59.9	60.1	52.6	60.5	59.5	60.8	60.0
(ii) सरकारी	11.6	11.2	11.1	10.9	12.2	10.5	10.4	10.7	11.0	10.5
सकल अचल पूंजी निर्माण	32.0	32.0	31.4	32.8	30.5	32.1	31.2	30.5	32.1	30.9
स्टॉक में परिवर्तन	3.5	3.5	3.6	3.6	3.3	3.4	3.5	3.4	3.6	3.5
निवल निर्यात	-7.2	-5.6	-7.7	-7.6	-3.8	-3.9	-8.6	-4.7	-7.7	-6.6
(रुपये बिलियन में)										
ज्ञापन:										
बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी	48693	52981	12126	12376	13702	14693	13154	13210		

* : त्वरित अनुमान । # : संशोधित अनुमान ।

नोट: चूंकि सारणी में केवल प्रमुख मदों को ही शामिल किया गया है, इसलिए आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं होगा।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ।

* ज्ञात सीमाओं के बावजूद, सकल मांग के घटकों के लिए व्यय-पक्षीय जीडीपी के आंकड़ों को प्रॉक्सी के रूप में उपयोग किया गया है।

कंपनियों के निवेश संबंधी रुचि में तेजी से गिरावट आई

II.3 2010-11 के दौरान पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में नई परियोजनाओं में कंपनियों के निवेश में 43 प्रतिशत की तेज गिरावट आई। 2011-12 की पहली तिमाही में यह लगभग उसी स्तर पर बना रहा परंतु दूसरी तिमाही में इसमें क्रमगत आधार पर फिर से तेज गिरावट आई। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के परियोजना वित्त संबंधी आंकड़े दर्शाते हैं कि 2011-12 की दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में स्वीकृत परियोजनाओं के कुल परिव्यय में लगभग 77 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी II.2)।

II.4 उद्योग-वार, बिजली तथा धातु एवं धातु उत्पाद क्षेत्र में नई निवेश योजनाओं के हिस्से में 2011-12 की दूसरी तिमाही में लगातार तेज गिरावट आई जबकि टेक्सटाइल तथा सीमेंट उद्योगों में सुधार देखा गया।

II.5 स्वीकृत परियोजनाओं के समय चरण-वार विवरण के अनुसार 2011-12 के दौरान निजी कंपनी (गैर-वित्तीय) क्षेत्र की संस्थागत सहायता तथा पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कम रहने की संभावना है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्याज दरों तथा कच्चे माल की लागत में हुई बढ़ोतरी ने निवेश संबंधी धारणा पर प्रतिकूल असर डाला है (सारणी II.3)।

बढ़ती लागत, घटती मांग के चलते कंपनियों के मार्जिन में गिरावट

II.6 2011-12 की दूसरी तिमाही में पिछली दो तिमाहियों की तुलना में बिक्री में मामूली गिरावट आई जो मांग के क्रमशः कम होते जाने को

सारणी II.2: संस्थाओं से सहायता प्राप्त परियोजनाएं और उनकी परिकल्पित लागत

अवधि	परियोजनाओं की संख्या*	परियोजनाओं की लागत (₹ बिलियन)	
1	2	3	
2009-10	ति1	150	914
	ति2	193	1,415
	ति3	175	1,402
	ति4	236	829
2010-11	ति1	199	1,431
	ति2	(231) 239	(1,495) 1,508
	ति3	173	801
	ति4	185	864
2011-12	ति1	(142) 144	(876) 880
	ति2**	167	339

*: 39 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर आधारित।

** : 2011-12 की दूसरी तिमाही के आंकड़े 36 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं। 2010-11 की दूसरी तिमाही और 2011-12 की पहली तिमाही के तदनु रूप आंकड़े कोष्ठकों में दिए गए हैं।

दर्शाती है (सारणी II.4)। ब्याज के भुगतान, स्टाफ लागत तथा कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि से निवल लाभ में गिरावट आई (सारणी II.5)। परंतु इन्वेंटरी का भंडार पिछली तिमाही तथा पिछले वर्ष की तदनु रूप तिमाही की तुलना में कम था (चार्ट II.1)।

II.7 आईटी कंपनियां इस प्रवृत्ति को बदलने में सफल रहीं तथा इन्होंने 22.2 प्रतिशत का निवल लाभ दर्ज किया (चार्ट II.2)। साथ ही, जहां बड़ी कंपनियों की बिक्री में सुदृढ़ वृद्धि हुई तथा लाभ मार्जिन में मामूली गिरावट आई वहीं छोटी कंपनियों में बिक्री तथा लाभ मार्जिन दोनों में गिरावट आई (चार्ट II.3)।

II.8 पचासी कंपनियों के 2011-12 की तीसरी तिमाही के प्रारंभिक परिणाम दर्शाते हैं कि बिक्री में वृद्धि की दर सुदृढ़ रही तथा परिचालन

सारणी II.3: बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा परियोजना मंजूरी सहायता का चरणबद्ध पूंजी व्यय

वर्ष जिसमें पूंजी व्यय किया गया →	2007-08 तक							(₹ बिलियन)	
	2007-08 तक	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 से आगे	सकल जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
स्वीकृति का वर्ष ↓									
2007-08 तक	1,826	1,317	583	376	98	47	-	4,247	
2008-09	265	1,029	864	568	366	84	46	3,223	
2009-10	2	448	1,494	1,282	853	365	116	4,560	
2010-11	-	3	373	1,262	1,294	979	691	4,602	
2011-12*	-	-	12	119	426	323	339	1,219	
सकल जोड़ #	2,093	2,797	3,326	3,607	3,037	1,798	1,192	-	

*: 2011-12 की दूसरी तिमाही तक के आंकड़े उपलब्ध हैं।

#: अनुमान प्रत्याशित हैं, इसमें केवल परिकल्पित निवेश शामिल है और इस प्रकार ये वास्तविक उपलब्धि/ उपयोग से भिन्न हैं।

सारणी II.4: कंपनी क्षेत्र - वित्तीय निष्पादन

मद	2010-11				2011-12	
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2
1	2	3	4	5	6	7
कंपनियों की संख्या	2023					
(वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दरें प्रतिशत में)						
बिक्री	25.8	19.9	18.2	20.5	22.6	19.3
व्यय	30.5	21.2	20.3	22.8	23.1	22.9
कच्चा माल	39.1	21.7	20.6	27.2	27.9	23.4
स्टाफ लागत	15.8	20.2	21.5	20.3	20.1	18.0
परिचालन लाभ (पीबीडीआईटी)	16.1	8.8	11.7	15.9	11.3	-0.6
अन्य आय*	-13.6	52.3	13.0	-24.1	41.5	31.7
मूल्यहास प्रावधान	20.9	17.3	13.9	14.5	9.0	9.8
ब्याज भुगतान	30.7	6.3	22.9	32.9	22.0	47.5
करोत्तर लाभ	3.8	9.8	11.2	13.4	9.4	-13.0
(अनुपात प्रतिशत में)						
बिक्री की तुलना में स्टॉक में परिवर्तन#	3.0	1.1	1.3	1.9	1.5	0.9
बिक्री की तुलना में परिचालन लाभ	16.5	15.9	16.0	15.3	14.9	13.2
बिक्री की तुलना में करोत्तर लाभ	8.6	8.8	8.5	8.6	7.7	6.4
बिक्री की तुलना में ब्याज	2.9	2.6	2.6	2.5	2.8	3.2
सकल लाभ की तुलना में ब्याज	20.6	18.8	19.4	19.1	21.9	27.7
ब्याज कवरेज (टाइम्स)	4.9	5.3	5.1	5.2	4.6	3.6

*: यदि असाधारण आय/व्यय का स्पष्टतः उल्लेख किया गया हो तो उसे अन्य आय में शामिल नहीं किया गया है।

#: इस मद की जानकारी स्पष्टतः सूचित करने वाली कंपनियों के लिए।

टिप्पणी: वृद्धि दरें कंपनियों के कॉमन सेट के लिए पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में संदर्भाधीन अवधि में स्तर में प्रतिशत परिवर्तन हैं।

लाभ (पीबीडीआईटी) तथा निवल लाभ (पीएटी) में हुई वृद्धि 2011-12 की दूसरी तिमाही की तुलना में अधिक थी।

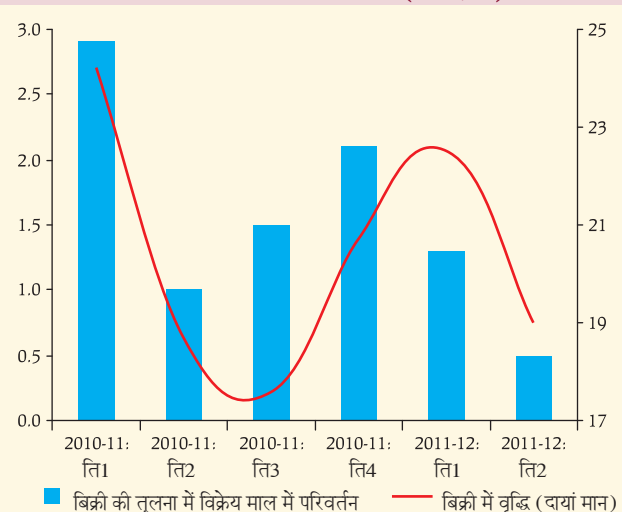
चक्रीय दबावों के साथ-साथ ढांचागत घाटे में वृद्धि होने से राजकोषीय गुंजाइश बाधित हुई

II.9 2011-12 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतकों में विस्तार हुआ जो चक्रीय तथा ढांचागत कारकों के

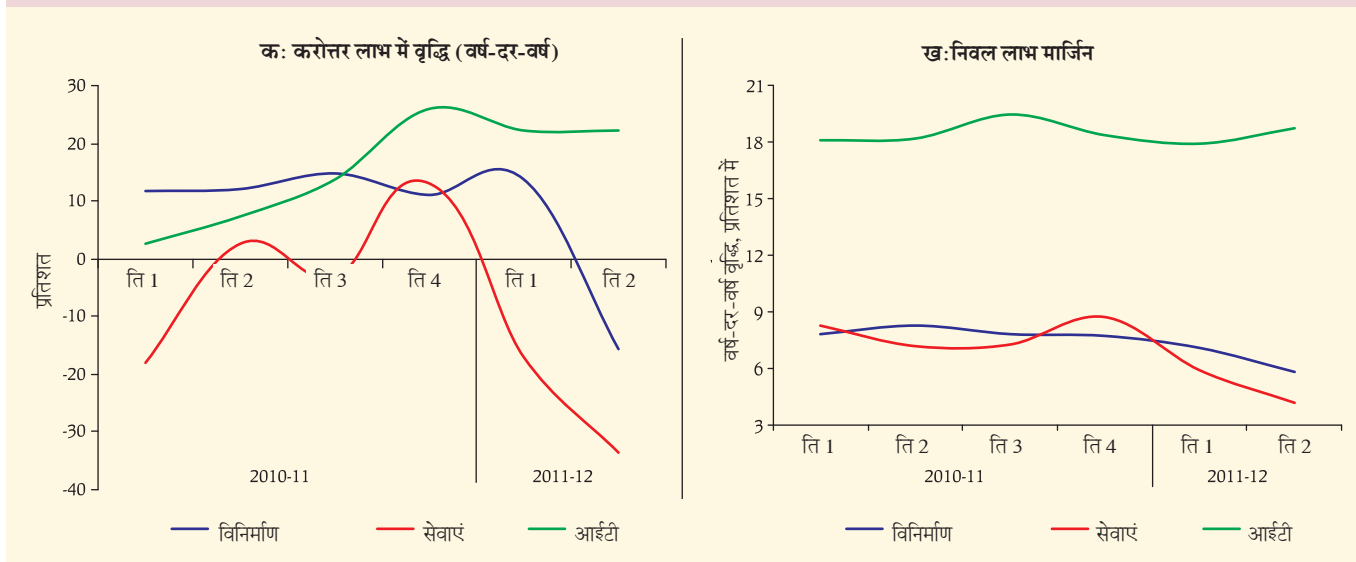
सारणी II.5: कारपोरेट क्षेत्र - वित्तीय निष्पादन - आनुक्रमिक

मद	सामान्य कंपनियों (तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि, प्रतिशत में)					
	वि.वर्ष 10 ति4 की तुलना में वि.वर्ष 11 ति1	वि.वर्ष 11 ति1 की तुलना में वि.वर्ष 11 ति2	वि.वर्ष 11 ति2 की तुलना में वि.वर्ष 11 ति3	वि.वर्ष 11 ति3 की तुलना में वि.वर्ष 11 ति4	वि.वर्ष 11 ति4 की तुलना में वि.वर्ष 12 ति1	वि.वर्ष 12 ति1 की तुलना में वि.वर्ष 12 ति2
1	2	3	4	5	6	7
कंपनियों की संख्या	2023					
बिक्री	-5.2	6.3	5.5	13.1	-3.3	3.4
व्यय जिसमें से	-3.6	5.0	5.6	14.8	-3.3	4.9
कच्चा माल	-4.4	2.0	9.0	17.5	-3.1	1.4
स्टाफ लागत	2.2	8.4	2.2	5.5	3.3	5.8
परिचालन लाभ (पीबीडीआईटी)	-1.9	2.3	6.6	7.8	-5.5	-8.4
अन्य आय	-43.8	36.1	-21.8	28.2	2.0	28.7
मूल्यहास	1.3	1.0	3.2	8.2	-3.7	1.9
ब्याज	15.9	-3.3	7.6	7.9	8.4	18.3
करोत्तर लाभ	-10.4	8.4	1.9	14.1	-13.4	-13.6

चार्ट II.1: बिक्री की तुलना में बिक्री वृद्धि उतार-चढ़ाव तथा विक्रेय माल में परिवर्तन (प्रतिशत)



चार्ट II.2: निवल लाभ



आपसी संबंधों को दर्शाता है। वृद्धि में आई कमी से कुल कर संग्रहण प्रभावित हुआ। यह इसलिए भी हुआ क्योंकि कर की वापसी की मात्रा काफी होने से प्रत्यक्ष कर संग्रहण की राशि कम रही तथा कंपनियों को लाभ भी कम हुआ। अर्थव्यवस्था की वृद्धि के चक्र का असर वर्षों के दौरान इस रूप में देखा जाता रहा है कि गिरावट के दौरान घाटे में बढ़ोतरी होती है तथा बहाली के दौरान उसमें कमी आती है (चार्ट II.4)।

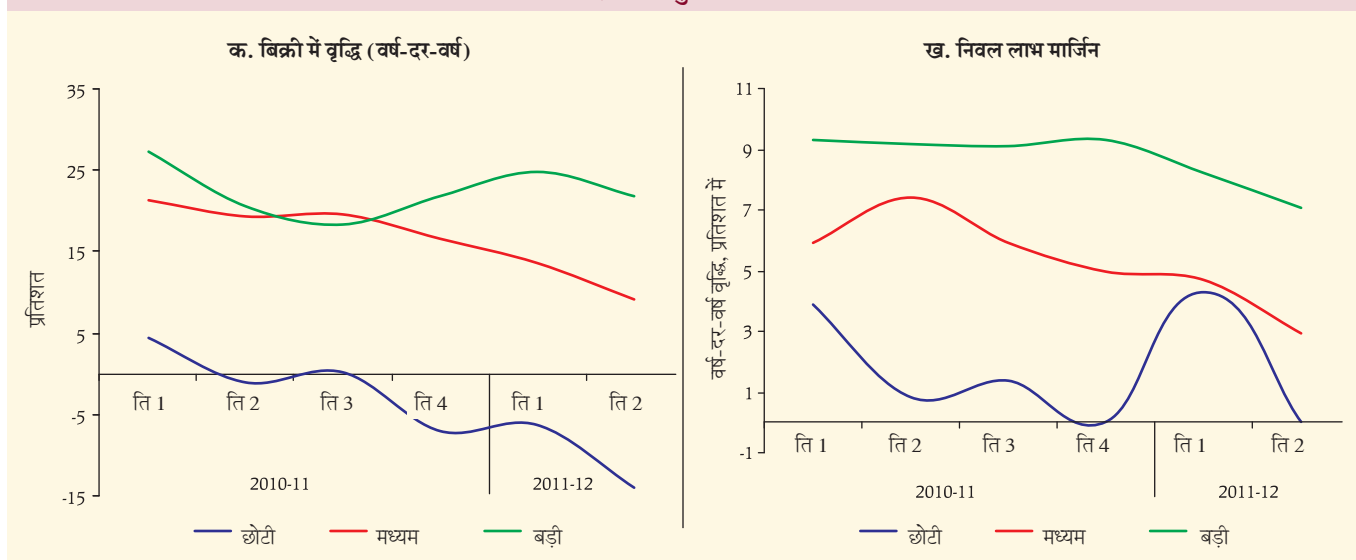
II.10 राजकोषीय असंतुलों से व्यय के पक्ष में ढांचागत जड़ताओं की स्थिति बनी रही जोकि बजट में सब्सिडी जैसे व्यय को कम करने

के निश्चय के बावजूद सरकार द्वारा उसे नियंत्रित न कर पाने के कारण थी। इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार एफआरबीएम में निर्धारित मध्य-वर्ष के लक्ष्य को पूरा न कर सकी। राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बजट अनुमान का 45 प्रतिशत से अनधिक तथा गैर-ऋण प्राप्तियों का लक्ष्य बजट अनुमान का न्यूनतम 40 प्रतिशत रखा गया था।

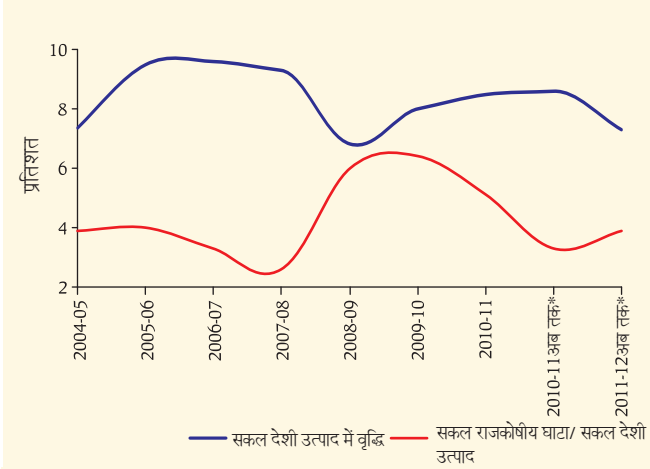
राजस्व लेखा का बढ़ता असंतुलन चिंता का विषय

II.11 राजस्व घाटे के बढ़ते स्तर से राजकोषीय दबाव की स्थिति बन रही है तथा यह पूंजीगत व्यय की सरकार की क्षमता को प्रभावित

चार्ट II.3: निष्पादन के प्रमुख संकेतक - आकार-वार



चार्ट II.4: वृद्धि चक्र और केंद्र के सकल देशी उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का अनुपात

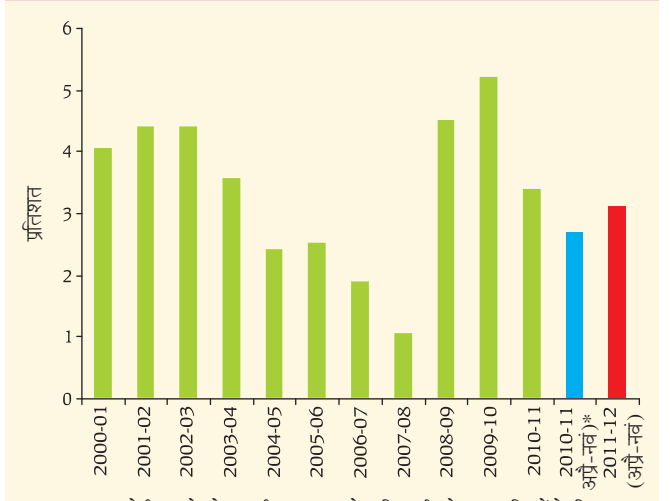


*सकल देशी उत्पाद में वृद्धि के लिए सितंबर तक और सकल राजकोषीय घाटा/ सकल देशी उत्पाद के अनुपात के लिए नवंबर तक के राजकोषीय वर्ष को दर्शाता है। 2010-11 के लिए, सकल राजकोषीय घाटे को बजटीय प्रावधान से अधिक की स्पेक्ट्रम प्राप्ति के लिए समायोजित किया गया है।

कर रहा है। केंद्र सरकार ने 2011-12 के बजट में जीडीपी की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात (3.4 प्रतिशत) में कोई बदलाव नहीं किया है और ऐसा इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि एक वर्ष पहले स्पेक्ट्रम की निलामियों से गैर-कर राजस्व के रूप में एकबारगी प्राप्त राशि इस वर्ष उपलब्ध नहीं होगी। तदनुसार सरकार ने राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व भुगतान दोनों की वृद्धि दर काफी कम रहने का अनुमान लगाया है। तथापि राजस्व व्यय में मामूली गिरावट आई जबकि राजस्व प्राप्ति की राशि में कमी आई। इसके परिणामस्वरूप, पहले 8 महिनों के दौरान राजस्व घाटा वार्षिक बजट लक्ष्य का 91.3 प्रतिशत रहा। इस प्रकार 2011-12 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान जीडीपी की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उच्चतर रहा, यहां तक कि स्पेक्ट्रम से मिलने वाली बजटीय निर्धारण से अधिक राशि के समायोजन के बाद भी यह अधिक है (चार्ट II.5)। यद्यपि 2011-12 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान सकल राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात, जोकि राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता की जांच के लिए महत्वपूर्ण आधार है, 2010-11 (अप्रैल-नवंबर) के 81.8 प्रतिशत के समायोजित अनुपात की तुलना में कम है, परंतु यह 2011-12 के पूरे वर्ष के बजटीय अनुपात (73.9 प्रतिशत) से अधिक है। यह स्थिति दर्शाती है कि राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधार की राशि के बड़े हिस्से का उपयोग किया जा रहा है जिससे पूंजीगत परिव्यय के लिए संसाधनों की उपलब्धता कम हो जाती है। इसका भारत की संभावित वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

II.12 2011-12 (अप्रैल-नवंबर) में कुल गैर-ऋण प्राप्ति में कमी आई, साथ ही कर राजस्व में हुई वृद्धि केंद्र सरकार के बजट में

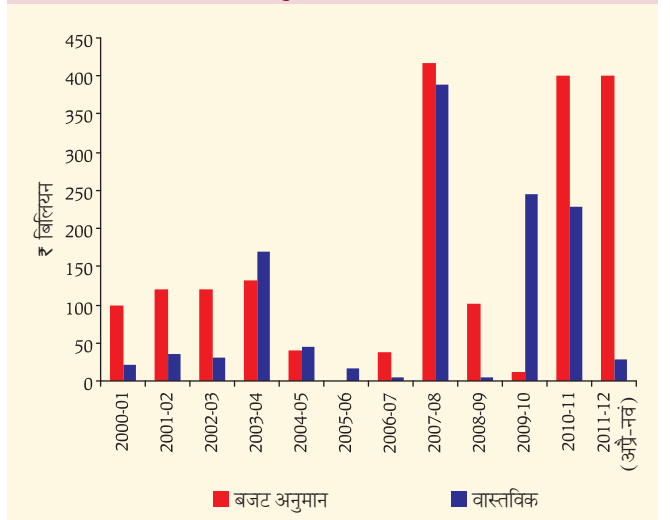
चार्ट II.5: केंद्र के सकल देशी उत्पाद की तुलना में राजस्व घाटे का अनुपात



*सकल राजकोषीय घाटे को बजटीय प्रावधान से अधिक की स्पेक्ट्रम प्राप्ति के लिए समायोजित किया गया है।

पुरानी परिपाटी के अनुसार किए गए अनुमानित वृद्धि से भी कम रही। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के बजटीय लक्ष्य से पीछे रह गई है (चार्ट II.6)। साथ ही इस बात की संभावना है कि व्यय बजटीय स्तर से अधिक हो जाएगा जैसा कि नवंबर 2011 की दूसरी अनुपूरक अनुदान मांगों में की गई अतिरिक्त मांग से स्पष्ट होता है। वर्तमान आकलन के अनुसार राजकोषीय घाटा 2011-12 के बजटीय अनुमान से जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत अधिक रह सकता है। उल्लेखनीय है कि यदि आर्थिक गिरावट आगे भी जारी रहती है तो राजकोषीय गिरावट के स्तर में वृद्धि होगी। केंद्र का मध्य-वर्ष की राजकोषीय स्थिति का

चार्ट II.6: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का विनिवेश - वास्तविक की तुलना में बजटीय प्रावधान



अपना विश्लेषण इस बात को स्वीकार करता है कि 2011-12 के घाटे के लक्ष्य को पूरा कर पाना एक चुनौती होगी।

II.13 भविष्य की ओर देखें तो, 2012-13 में राजकोषीय स्थिति में सुधार न केवल वृद्धि की स्थिति पर निर्भर करेगा बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कर और व्यय सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति कैसी रहती है। प्रत्यक्ष कर कोड बिल (जो वर्तमान में वित्तीय विषय पर स्थायी समिति के विचाराधीन है) के अधिनियमन में हुई देरी से इसे लागू करने की 1 अप्रैल 2012 की नियत तारीख में बदलाव करना होगा। वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में स्थिति यह है कि जहां इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन संबंधी बिल मार्च 2011 में प्रस्तुत किया गया था वहीं जीएसटी विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों से जुड़े कई मुद्दों पर सहमति की आवश्यकता होगी। व्यय के पक्ष में, पेट्रोलियम सब्सिडियों पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने के लिए सरकार को डीजल की कीमतों से नियंत्रण हटाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि राजकोषीय सुधार में तेजी नहीं लायी जाती है तो केंद्र सरकार 2011-12 के केंद्रीय बजट में निर्धारित 2012-13 के राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 4.1 प्रतिशत के रोलिंग लक्ष्य से पीछे रह सकती है।

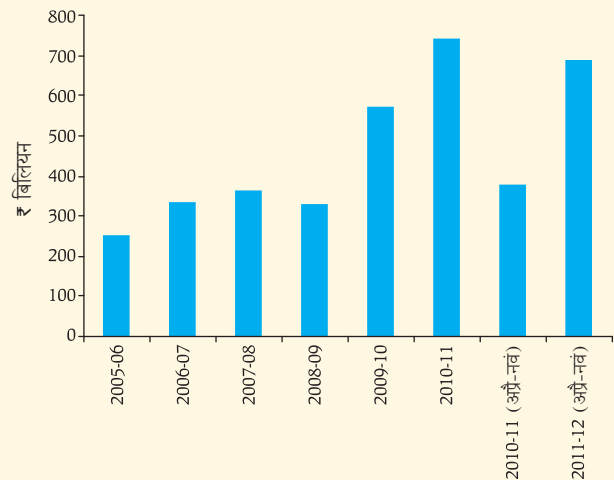
कर राजस्व 2011-12 के बजटीय लक्ष्य से कम पड़ सकता है, आगे की बेहतर वृद्धि और सुधार पर निर्भर करेगा

II.14 2011-12(अप्रैल-नवंबर) के दौरान कर राजस्व की वृद्धि दर में गिरावट आई जो प्रत्यक्ष कर की भारी वापसी, पेट्रोलियम उत्पादों के शुल्क में की गई कमी तथा आर्थिक वृद्धि दर में आई गिरावट की वजह से है। कंपनी कर राजस्व की वृद्धि दर में तेज गिरावट देखी गई जो करों की वापसी तथा औद्योगिक कार्यकलापों में आई गिरावट की वजह से थी। चालू वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष करों की भारी वापसी दर्शाती है कि 2010-11 के दौरान जो राजकोषीय सुधार हुआ वह कुछ हद तक करों के अतिरिक्त संग्रहण के कारण था जिनकी वापसी चालू वर्ष में अब तक की गयी (चार्ट II.7)। चालू वर्ष में अब तक की परोक्ष कर की समग्र वृद्धि बजट में निर्धारित वृद्धि दर के अनुरूप रही है।

सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि कंपनियों के चालू निवेश के कम होने से बहाली में देरी हो सकती है

II.15 निजी निवेश के प्रति रुचि कम होने और सार्वजनिक निवेश में कमी आने से आर्थिक वृद्धि की बहाली में और देरी हो सकती है। 2011-12 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान योजना व्यय (राजस्व तथा

चार्ट II.7: प्रत्यक्ष कर वापसी



स्रोत: प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

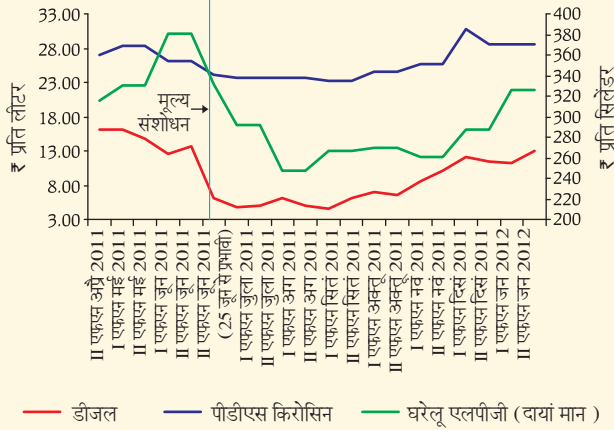
पूंजी दोनों) की वृद्धि दर पूरे वर्ष की बजटीय वृद्धि दर से धीमी थी। पूंजी परिव्यय की वृद्धि दर एक वर्ष पूर्व की तदनु रूप अवधि की तुलना में कम थी। यह कमी मुख्यतः ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण एवं पेय जल आपूर्ति जैसे विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के योजना व्यय की राशि कम रहने की वजह से थी।

सब्सिडी के चलते अवहनीय दबाव बन रहा है, प्रतिबद्धता के बेहतर निष्पादन के लिए बजटीय समाधान की जरूरत है

II.16 चालू राजकोषीय वर्ष में अब तक सकल व्यय की वृद्धि दर में जो गिरावट आयी वह मुख्यतः योजना व्यय की वृद्धि दर कम रहने की वजह से थी। दूसरी ओर, गैर-योजना व्यय में उच्च वृद्धि हुई जो प्रमुख सब्सिडियों और ब्याज भुगतानों में उच्चतर व्यय की वजह से थी।

II.17 डीजल तथा पीडीएस किरोसिन की बिक्री की प्रति इकाई कम वसूली, जिसमें दिसंबर 2011 की दूसरी छमाही में गिरावट आई थी, की राशि में जनवरी 2012 में कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों के बढ़ने तथा रुपये के कमजोर पड़ने के अनुरूप वृद्धि हुई (चार्ट II.8)। वर्तमान संकेतकों के अनुसार तेल विपणन कंपनियों की नियंत्रित कीमत वाले पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर होने वाली कम वसूली की राशि 2011-12 में 1,323 बिलियन रुपये रहने का अनुमान किया गया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए किए गए बजट प्रावधान को पहले ही खत्म कर लिया है और नवंबर 2011 में प्रस्तुत

चार्ट II.8: तेल विपणन कंपनियों की उत्पाद की प्रति इकाई की कम वसूली



टिप्पणी: I एफएन: पहला पखवाड़ा II एफएन: दूसरा पखवाड़ा
स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

किये गये दूसरी अनुपूरक अनुदान मांग में अतिरिक्त प्रावधान (300 बिलियन रुपये) का उल्लेख किया है। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए किए गये उच्चतर व्यय के कारण 2011-12 में राजकोषीय घाटे में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल के अधिनियमन तथा कार्यान्वयन के बाद खाद्य सब्सिडी के क्षेत्र में सरकार पर अधिक दबाव पड़ेगा। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को पेट्रोलियम सब्सिडी पर होने वाले व्यय को कम करना होगा। इसके चलते नियंत्रित कीमत वाले पेट्रोलियम उत्पादों से नियंत्रण को और कम करना होगा।

राज्यों के संशोधित एफआरबीएम से नियम आधारित राजकोषीय समेकन परिलक्षित होता है

II.18 2011-12 में राज्यों के बजट में समेकित राजस्व लेखा अधिशेष में रहने का अनुमान किया गया है जोकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा परिकल्पित राजकोषीय समेकन की ओर आगे बढ़ने का संकेत है। राजस्व लेखा में हुए सुधार, जोकि मुख्यतः राजस्व व्यय में कटौती के कारण है, से न केवल पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होगा बल्कि जीडीपी की तुलना में जीएफडी के अनुपात को कम करने में भी मदद मिलेगी जिसमें 0.4 प्रतिशत अंक की गिरावट का अनुमान किया गया है। राज्यों के लिए यह जरूरी था कि वे राजस्व घाटे को समाप्त करने की रूपरेखा तैयार करें तथा 2014-15 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पादके तीन प्रतिशत तक करने की दिशा में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) में संशोधन करें ताकि वे एनएसएसएफ ऋणों पर अनुदान तथा ब्याज राहत के लिए पात्र हो

सकें। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने एफआरबीएम अधिनियमों में पहले ही संशोधन कर लिए हैं।

II.19 बजटीय असंतुलों को कम करने की प्रतिबद्धता के बावजूद राज्य सरकारों की बढ़ती आकस्मिक देयताएं, विशेष रूप से राज्य बिजली सेवाओं के एक्सपोजर, राज्य वित्त के लिए चिंता के क्षेत्र के रूप में उभरी हैं। वितरण सेवाओं की वित्तीय स्थिति पर उच्च-स्तरीय पैनल (अध्यक्ष: श्री वी.के.शुंगलु) ने योजना आयोग को हाल में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि 2005-10 के दौरान बिजली वितरण कंपनियों की समेकित हानियां 820 बिलियन रुपये थीं। हानि की राशि का 70 प्रतिशत से भी अधिक का सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्तपोषण किया गया था जबकि इन ऋणों के 42 प्रतिशत के लिए राज्य सरकार ने गारंटी दी थी। चूक होने पर यदि राज्य सरकार की गारंटियां लागू की जाती हैं तो राज्य वित्त पर इसका भारी असर पड़ेगा क्योंकि राज्यों की गारंटी चुकौती निधि में उपलब्ध राशि (40 बिलियन रुपये) अपर्याप्त है।

राजकोषीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन जरूरी है क्योंकि बाजार उधारियों पर बढ़ती निर्भरता चिंताजनक बात है

II.20 केंद्र सरकार ने वर्तमान राजकोषीय वर्ष में अब तक सकल राजकोषीय घाटे एवं सार्वजनिक लेखाओं से किए गए आहरणों का वित्तपोषण राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में निवल राशि के कम रहने के कारण मुख्यतः बाजार उधारियों के जरिए किया। अर्थोपाय अग्रिमों का भी सहारा लिया गया जिसके चलते घाटे का मौद्रीकरण हुआ। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा नकद राशि का आहरण तथा अतिरिक्त नकदी का विनिवेश किया गया (सारणी II.6)। केंद्र सरकार ने 2011-12 की दूसरी छमाही के लिए बाजार उधार के लक्ष्य में दो बार बढ़ोतरी की जिससे 2011-12 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए सकल बाजार उधार बजटीय राशि से 22.3 प्रतिशत अधिक रहा। केंद्र सरकार ने घाटे के वित्तपोषण के लिए खजाना बिलों का भी सहारा लिया। सरकारी उधार के अधिक होने से प्रतिफल में वृद्धि होती है तथा निजी निवेश के लिए घरेलू निधीयन के स्तर में कमी आती है।

2012-13 में स्थिति में बेहतरी के लिए सुधारों की जरूरत है

II.21 चालू खाते के घाटे के साथ-साथ सामान्य समष्टि आर्थिक कमजोरी की स्थिति में बड़ी मात्रा में राजकोषीय व्यय से देश की वृद्धि तथा स्थिरता और अधिक प्रभावित हो सकती है। वर्तमान तथा

सारणी II.6: केंद्र सरकार के सकल राजस्व घाटे के वित्तपोषण के स्रोत

(जीएफडी में प्रतिशत हिस्सा)

मद	अप्रै-नव 2011	अप्रै-नव 2010
1	2	3
बाजार उधार	97.0	140.1
राज्य भविष्य निधि	0.9	2.3
राष्ट्रीय लघु बचत निधि	2.6	7.9
नकदी शेष {(कमी (+)/वृद्धि(-)}	0.5	-13.7
नकदी अधिशेष का निवेश(-)/विनिवेश(+)	4.6	-17.1
बाह्य सहायता	1.8	7.8
अर्थोपाय अग्रिम	5.6	0.0
अन्य *	-13.1	-27.3

* इसमें विशेष जमाराशियां, उचंत और विप्रेषण और अन्य पूंजी प्राप्तियां जैसी मदें शामिल हैं।

स्रोत: लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भविष्य की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकारी खपत व्यय को कम करने तथा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने की जरूरत है। इससे अर्थव्यवस्था को वृद्धि के उस संभावित स्तर तक ले जाने में मदद मिलेगी जिसे संकट से पूर्व की अवधि में इसने प्राप्त किया था।

II.22 पूर्वानुमान के अनुसार 2011-12 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति के कम होने और मौद्रिक दर के चक्र के ऊंचे स्तर तक

पहुंचने से कारोबारी उत्साह में बेहतरी आ सकती है। विशेष रूप से ऐसी बेहतरी तब आ सकती है जब राजकोषीय असंतुलन नियंत्रित हो ताकि मौद्रिक पक्ष को अधिक गुंजाइश दिया जा सके। वैश्विक अनिश्चितता तथा घरेलू वृद्धि की संभावनाओं पर इसके असर से जुड़े जोखिमों के चलते 2012-13 में जहां कर राजस्व प्रभावित हो सकता है वहीं 2012-13 के केंद्रीय बजट के 10.8 प्रतिशत के सकल कर राजस्व-जीडीपी अनुपात के रोलिंग लक्ष्य को प्राप्त किया जाना प्रत्यक्ष कर कोड के समय पर कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। यह आशा की जाती है कि प्रत्यक्ष कर कोड प्रणाली से अनुपालन के स्तर में सुधार होगा क्योंकि इसके तहत कंपनी कर तथा अधिभार में कमी आएगी तथा कर का आधार व्यापक होगा। जहां वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में काफी अनिश्चितता बनी हुई है वहीं इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सहमति बनाने की जरूरत है ताकि अनुपालन की दिशा में और सुधार लाया जा सके तथा संकट से पूर्व की कर की बेहतरी की स्थिति को प्राप्त किया जा सके। अल्पावधि में विनिवेश जैसे अस्थायी उपायों पर निर्भरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परंतु इस संबंध में बनाई जाने वाली योजना बाजार की स्थितियों के अनुसार होनी चाहिए ताकि राजस्व की प्राप्ति वर्ष के दौरान होती रहे। इसके अलावा, राजस्व के क्षेत्र में किए जाने वाले सुधारों के साथ-साथ सब्सिडियों को रोकने की दिशा में भी उपाय किए जाने चाहिए ताकि इनका निर्धायन वहनीय आधार पर बजट से किया जा सके।